भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 2588
दिनांक 14 दिसम्बर, 2021 के लिए प्रश्न

पशुपालन हेतु विकास योजनाएं

2588. डॉ. सुकान्त मजूमदारः
श्री. ज्योतिर्मय सिंह महतोः

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी परियोजनाओं की स्थापना के संबंध में पश्चिम बंगाल राज्य सहित कुछ राज्यों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल राज्य सहित देश में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी क्षेत्र के विकास के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित का जा रही विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन योजनाओं से अब तक लाभान्वित हुए किसानों की कुल संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी क्षेत्र में विकास दर के लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) देश में पशुपालन और मत्स्य पालन जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं; और

(च) डेयरी की स्थापना के लिए पशुपालकों को प्रदान की जा रही सहायता और सुविधाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री परशोत्तम रूपाला)

(क) और (ख): सरकार को विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी परियोजनाओं की स्थापना के लिए पश्चिम बंगाल सहित राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल सहित देश में मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी क्षेत्र के विकास हेतु सरकार द्वारा लागू की जा रही विभिन्न योजनाओं का विवरण इस प्रकार है:

i. राष्ट्रीय गोकुल मिशन
ii. राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम
iii. राष्ट्रीय डेयरी योजना (29 नवम्बर, 2019 को समाप्त)
iv. डेयरी उद्यमिता विकास योजना (2020-21 से बंद)
v. डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि
vi. डेयरी कार्यकलापों में लगी डेयरी सरकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों की सहायता
vii. राष्ट्रीय पशुधन मिशन
viii. पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण
ix. पशुधन अवसंरचना विकास निधि
x. राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम
xi. पशुधन संगणना और एकीकृत नमूना सर्वेक्षण
xii. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना
xiii. मत्स्यपालन और जलकृषि अवसंरचना विकास निधि

(ग) राष्ट्रीय गोकुल मिशन लाभार्थी उन्मुख योजना नहीं है। तथापि, दुग्ध उत्पादकता में वृद्धि के रूप में शामिल सभी गोपशु और भैंस पालकों को योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है।

एनपीडीडी के तहत, कुल 5,05,503 दुग्ध उत्पादक कवर किये गये हैं। एनडीपी-I के तहत, 16.88 लाख से अधिक दुग्ध उत्पादकों को बाजार पहुंचे प्रदान की गई। समग्रत: परियोजना ने 97,000 गावों में लगभग 59 लाख लाभार्थियों को कवर किया। डीईडीएस के तहत 4,21,158 लाभार्थियों की 1892.29 करोड़ रू. की सब्सिडी राशि के साथ सहायता की गई।

एनएलएम के तहत, कुक्कुट विकास घटक के अंतर्गत 47,550 किसान, हस्त और विद्युत चालित चाफ कटर का वितरण और सिलेज निर्माण यूनिट घटक के तहत 72,175 किसान लाभान्वित हुए हैं। ग्रामीण घरेलू भेड़ और बकरी विकास के तहत, लाभार्थियों की संख्या 33,370 है। ग्रामीण घरेलू सुधार विकास के तहत, लाभार्थियों कीक संख्या 18,853 है। पशुधन बीमा के तहत 28,34,308 किसान और प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण के तहत 3,72,018 किसान लाभान्वित हुए हैं।

एनएडीसीपी कार्यक्रम के तहत लगभग 6.46 करोड़ किसान खुरपका एवं मुंहपका रोग के लिए अपने पशुओं के टीकाकरण के रूप में लाभान्वित हुए हैं। अब तक, टीकाकरण के पहले चक्र में, राज्यों से प्राप्त सूचना के अनुसार देश में एफएमडी के लिए 16.91 करोड़ पशुओं का टीकाकरण हो चुका है और 21.73 करोड़ पशुओं का ईयर-टैग किया जा चुका है। एफएमडी के लिए टीकाकरण का अगला चक्र शुरू हो चुका है। और अब तक 3.13 करोड़ पशुओं का टीकाकरण किया जा चुका है। ब्रूसेला के लिए भी टीकाकरण शुरू कर दिया गया है और अब तक 25.87 लाख पशुओं का टीकाकरण किया जा चुका है।

(घ) देश में दुग्ध उत्पादन पिछले 6 वर्षों के दौरान 6.28% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रहा है। राष्ट्रीय लेखा संख्यिकीय के अनुसार, वर्ष 2019-20 में दूध के उत्पादन का मूल्य 8.39 लाख करोड़ रू. (चालू मूल्यों पर) अनाज से उत्पादन के कुल मूल्य से अधिक है। पिछले तीन वर्षों के दौरान वार्षिक वृद्धि दर (एजीआर) के साथ मत्स्यपालन का वर्ष-वार उत्पादन इस प्रकार है:

वर्ष	**मत्स्य**	
	मात्रा लाख टन में	**एजीआर %**
2017-18	127.04	11.13
2018-19	135.73	6.84
2019-20	141.64	4.35

भारत सरकार पशुपालन और मत्स्यपालन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को संपूरित करने के लिए विभिन्न योजनाएं नामत: राष्ट्रीय गोकुल मिशन, राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय डेयरी योजना (29 नवम्बर, 2019 को समाप्त), डेयरी उद्यमिता विकास योजना (2020-21 से बंद), डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि, डेयरी कार्यकलापों में लगी डेयरी सरकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों की सहायता, राष्ट्रीय पशुधन मिशन, पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण, पशुधन अवसंरचना विकास निधि, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, पशुधन संगणना और एकीकृत नमूना सर्वेक्षण, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मत्स्यपालन और जलकृषि अवसंरचना विकास निधि (क) और (ख) लागू कर रही है।

हाल ही में, सरकार ने देश में पशुपालन और डेयरी क्षेत्र बढ़ावा देने के लिए विभाग की योजनाओं संशोधित और पुनर्गठित किया है, जिसमें गोपशु, डेयरी, कुक्कुट, भेड़, बकरी, सुअरपालन, आहार एवं चारा क्षेत्र में हब स्पोक मॉडल के माध्यम से 50% सब्सिडी देकर, मोबाइल पशुचिकित्सा यूनिट की संस्वीकृति के माध्यम से 10 करोड़ पशुपालकों के लिए पशुचिकित्सा सेवाओं की द्वार पर आपूर्ति और तीव्र नस्ल सुधार के लिए आधुनिक

प्रौद्योगिकी का उपयोग करके ग्रामीण युवाओं और पशुपालकों के लिए आय सृजन हेतु बेहतर रोजगार अवसरों का निर्माण करके ग्रामीण उद्यमिता विकास पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

सरकार मत्स्यपालन और जलकृषि क्षेत्र को बढ़ाकर देने और उसके समग्र विकास के लिए भी विभिन्न योजनाएं लागू कर रही है। ये योजनाएं मत्स्यपालन अवसंरचना के निर्माण और रोजगार सृजन में मदद करेंगी।

(छ) गोपशु पालकों को डेयरी की स्थापना के लिए निम्नलिखित योजनाओं के तहत सहायता और सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं:

i. राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम
ii. डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि
iii. डेयरी कार्यकलापों में लगी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों की सहायता

****